(एक महारत्न कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय:"ऊर्जानिधि", 1 बाराखंभा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
सीआईएन: L65910DL1986GOI024862

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,7,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 1-4, इफको
चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम – 122001
सीआईएन : L40101011969G01005095

दिनांक: 12.02.2026

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department,Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (E) **Mumbai- 400 051.** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग , एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-**400 051**	**BSE Limited,** Department of Corporate Services,Floor -25, PJ Towers, Dalal Street, **MUMBAI - 400 001.** बीएसई लिमिटेड कॉर्पोरेट सेवा विभाग, मंजिल -25, पी.जे.टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-**400 001**

विषय: सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार सूचना- पीएफसी आरईसी पुनर्गठन के संबंध में एक संक्षिप्त अद्यतन

महोदय / महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के संदर्भ में और हमारी पूर्व सूचना दिनांक 06.02.2026 के अनुक्रम में, कृपया पीएफसी-आरईसी पुनर्गठन के संबंध में संक्षिप्त अद्यतन निम्नलिखित है:

क. पृष्ठभूमि

1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में, माननीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी के बीच पैमाने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (आरईसी) (जिसे इसके बाद दोनों संस्थाओं के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के पुनर्गठन के प्रस्ताव की घोषणा की।

उपरोक्त घोषणा के अनुसरण में, पीएफसी और आरईसी के बोर्डों ने 6 फरवरी 2026 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में पीएफसी और आरईसी के विलय के रूप में पुनर्गठन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि विलयित के बाद बनी इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों के तहत एक "सरकारी कंपनी" बनी रहे।

भारत सरकार की मंजूरी (पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 6 दिसंबर, 2018) के अनुरूप, पीएफसी ने 2019 में आरईसी में 52.63% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की थी, जिसके परिणामस्वरूप आरईसी, पीएफसी की एक सहायक कंपनी बन गई थी।

अब, समेकन की दिशा में यह नई गति रणनीतिक क्षेत्र में निरंतरता को दर्शाती है।

यह प्रस्तावित विलय विद्युत क्षेत्र की विकसित हो रही वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल, केंद्रित संस्थान बनाने की दिशा में आगे की ओर अग्रसर होने का प्रतिनिधित्व करता है।

ख. पीएफसी आरईसी विलय पर तालमेल

जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र को पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। समेकित आधार पर, विलय के बाद बनी इकाई को बेहतर बैलेंस शीट, पूंजी दक्षता और परिचालन तालमेल से लाभ होने की उम्मीद है, जिससे विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर वित्त पोषण और ऋण प्रवाह में सुधार संभव हो सकेगा।

आगे बढ़ते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा के अतिरिक्त, क्षेत्र का अगला चरण ग्रीन हाइड्रोजन, सीसीयूएस, छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर, ऊर्जा भंडारण समाधान जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होगा। एक संयुक्त इकाई के रूप में, इसके पास मजबूत तकनीकी क्षमताएं, गहरा क्षेत्र विशेषज्ञता होगी, जिसका लाभ इन उभरते अवसरों का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए उठाया जाएगा।

समेकित आंकड़ों के आधार पर, विलय के बाद बनी यह इकाई भारत में विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी वित्तपोषक संस्था के रूप में स्थापित होगी।

ग. प्रस्तावित विलय से संबंधित प्रमुख पहलू

i. **सरकारी इकाई की स्थिति:** विलयित इकाई एक सरकारी कंपनी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगी और भारत सरकार विलयित इकाई पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगी, जिसमें इसके बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति / हटाने का अधिकार भी शामिल है।

ii. **विलय कार्यान्वयन:** विलय संरचना विचाराधीन है। विलय के संरचित, समयबद्ध और अनुपालन निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बाहरी एजेंसियों को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें सलाहकार, मूल्यांकन विशेषज्ञ और कानूनी सलाहकार शामिल होंगे, जो लागू नियामक अनुमोदन के अधीन हैं।

iii. **ऋण व्यवसाय:** दोनों संस्थाएं, एनबीएफसी के रूप में, एकल और समूह उधारकर्ता जोखिमों पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एकाग्रता मानदंडों का अनुपालन करती हैं, जो टियर 1 पूंजी से जुड़े हैं। वर्तमान में, दोनों संस्थाएं निर्धारित जोखिम सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से काम कर रही हैं।

विलय के बाद, ये सीमाएं विलय वाली इकाई की समेकित टियर 1 पूंजी पर लागू होंगी। दोनों संस्थाओं की मजबूत निवल संपत्ति को देखते हुए, उधारकर्ता जोखिम मानदंडों के संबंध में किसी भी उल्लंघन की आशंका नहीं है। यह उम्मीद की जाती है कि विलय के बाद बनी इकाई भविष्य में ऋण वृद्धि को समर्थन देने के लिए पर्याप्त और आरामदायक पूंजी स्तर बनाए रखेगी।

iv. उधार जोखिम :

वर्तमान में, दोनों संस्थाओं के बकाया उधार मिश्रण में लगभग 18% घरेलू बैंक / एफआई के उधार, 25% विदेशी मुद्रा उधार और 57% घरेलू बाण्ड उधार शामिल हैं।
अधिग्रहण से पहले, दोनों संस्थाएं प्रत्येक 20% की एकल-इकाई जोखिम सीमा (संयुक्त सीमा 40%) के अधीन थीं। 2019 में आरईसी में अपनी हिस्सेदारी पीएफसी को बेचने के लिए भारत सरकार के बाद, आरबीआई के बड़े जोखिम ढांचे (एलईएफ) के तहत संयुक्त जोखिम को संबंधित बैंकों की टियर 1 पूंजी के 25% की समूह सीमा पर सीमित कर दिया गया था, जिसकी तुलना में पहले कुल सीमा 40% थी। दोनों संस्थाओं के लिए विविध वित्तपोषण मार्गों तक पहुंच पर विचार करते हुए, कम जोखिम सीमा में परिवर्तन को सुचारू रूप से प्रबंधित किया गया था। इसके अलावा, पांच वर्षों से अधिक समय से, दोनों संस्थाएं लागू समूह सीमाओं के भीतर सहजता से कार्य कर रही हैं।

विलय के पश्चात, विलय के बाद बनी इकाई पर 20% की एकल-इकाई एक्सपोजर सीमा लागू होगी।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 31 मार्च, 2025 की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, भारत के शीर्ष दस बैंकों की कुल टियर-I पूंजी लगभग 18 लाख करोड़ रुपये है, जो लाभ वृद्धि के कारण और आगे बढ़ेगी। इसे और दोनों संस्थाओं के वर्तमान बैंक ऋणों को देखते हुए, हमारा मानना है कि अतिरिक्त उधार लेने के लिए पर्याप्त गुंजाइश उपलब्ध होगी।

उपरोक्त को और उपलब्ध कई वित्तपोषण विविध मार्गों को देखते हुए, हम बिना किसी भौतिक बाधा के इस परिवर्तन को सुचारू रूप से प्रबंधित करने की उम्मीद करते हैं।

यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत किया गया है

धन्यवाद,

भवदीय,

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से
Digitally Signed
(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com

भवदीय,
आरईसी लिमिटेड
के लिए
Digitally Signed
(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
complianceofficer@recindia.com